अपीलीय सिविल

ए. बिफोरस ए. आई.डी रोशल, न्यायमूर्ती के समक्ष

एसएएमडीयू - *अपीलकर्ता।*

बनाम

सुभान खान आदि- *उत्तरदाता।*

1960 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 1529

3 नवंबर, 1971

*इक्वैक्यूई इंटरेस्ट (पृथक्करण) अधिनियम (*1951 *का एलएक्सआईवी) - धारा* 2 (डी*) और* 20 (1) *- मुकदमा जो "समग्र संपत्ति" से संबंधित नहीं है - इस* तरह के मुकदमे पर विचार करने के लिए सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र - क्या प्रतिबंधित है।

विस्थापित संपत्ति अधिनियम का प्रशासन (1950 का XXXI) - धारा 2 (एफ) और 46 (ए) - संरक्षक में विस्थापित संपत्ति का अधिकार - *सिविल कोर्ट द्वारा निर्धारण - क्या प्रतिबंधित है।*

*सिविल प्रक्रिया संहिता (*1908 का अधिनियम संख्या V) - *धारा* 80 *- मुकदमे में शिकायत न किए जाने वाले लोक अधिकारी का अधिनियम - ऐसा अधिकारी - चाहे नोटिस का हकदार हो - विस्थापित संपत्ति के गिरवी धारक द्वारा मुकदमा जो निर्धारित अवधि के भीतर बंधक के मोचन न होने के कारण उसका मालिक बनने की घोषणा की मांग करता है - मुकदमे में शामिल होने के बावजूद अभिरक्षक को नोटिस नहीं दिया जाता है - ऐसा मुकदमा - क्या निषिद्ध है।*

*परिसीमा अधिनियम (*1908 का IX) - *धारा* 19 *- बंधक अधिकारों के रूप में खरीदे गए या हस्तांतरित किए गए अधिकारों का विवरण देते हुए ग्राम पटवारी को रिपोर्ट देने वाला व्यक्ति - ऐसा विवरण - क्या बंधक के निर्वाह की स्वीकृति के बराबर है।*

यह माना गया कि इससे पहले कि विस्थापित हित (पृथक्करण) अधिनियम, 1951 की धारा 20 की उप-धारा (1) में रोक लागू हो सके, अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि विचाराधीन मुकदमा धारा 2 (डी) में परिभाषित "समग्र संपत्ति" के किसी भी दावे से संबंधित है और दावा अधिनियम की धारा 2 (बी) के दायरे में आता है। धारा 2 (डी) के अर्थ के भीतर "समग्र संपत्ति" का गठन करने के लिए, संपत्ति या उसमें किसी भी हित को विस्थापित संपत्ति घोषित किया जाना चाहिए या विस्थापित संपत्ति अधिनियम, 1950 के प्रशासन के तहत संरक्षक में निहित होना चाहिए। इस अधिनियम की धारा 8 (2) के अनुसार, जब तक किसी संपत्ति को विस्थापित संपत्ति अध्यादेश, 1949 प्रशासन की धारा 7 के प्रावधानों के अनुपालन में विस्थापित संपत्ति घोषित नहीं किया जाता है, तब तक इसे संरक्षक में निहित माना जा सकता है यदि यह किसी ऐसे व्यक्ति की संपत्ति है जो पूर्वी पंजाब विस्थापित संपत्ति (प्रशासन) अध्यादेश की तारीख से पहले विस्थापित हो गया था। 1949 को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार, जहां एक मुकदमे में विवाद में भूमि या उसमें बंधकों के अधिकारों को न तो विस्थापित संपत्ति घोषित किया जाता है

न ही उस तारीख को ज्ञात है जिस पर बंधककर्ता विस्थापित हो गए, ऐसी भूमि या उसमें बंधकों के अधिकार "समग्र संपत्ति" का गठन नहीं करते हैं। इसलिए ऐसी संपत्ति से संबंधित मुकदमे पर विचार करने के लिए सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को विस्थापित हित (पृथक्करण) अधिनियम, 1951 की धारा 20 के प्रावधानों के कारण प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।

और रूप कि विस्थापित संपत्ति अधिनियम, 1950 प्रशासन की धारा 8 में नियोजित भाषा यह स्पष्ट करती है कि भले ही कोई संपत्ति अधिनियम की धारा 2 के खंड (एफ) के अर्थ के भीतर "विस्थापित संपत्ति" हो सकती है, लेकिन इसे संरक्षक में निहित नहीं माना जाएगा जब तक कि इसे ^ या तो अधिनियम की धारा 7 के तहत विस्थापित संपत्ति घोषित नहीं किया गया था या किसी भी कानून के तहत संरक्षक में निहित नहीं किया गया था। अधिनियम द्वारा। इस प्रकार किसी संपत्ति के खाली की गई संपत्ति होने का प्रश्न अभिरक्षक में निहित संपत्ति से अलग है और बाद वाले को अधिनियम की धारा 46 के खंड (ए) द्वारा प्रतिबंधित किए गए मनोरंजन या निर्णय के प्रश्न के रूप में नहीं माना जा सकता है। (पैरा 25)

यह माना गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 द्वारा बनाई गई बार किसी सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ मुकदमे के मामले में केवल तभी संचालित

होती है जब ऐसा मुकदमा ऐसे सार्वजनिक अधिकारी के 'किसी भी कार्य के संबंध में' होता है। यदि किसी मुकदमे में किसी सार्वजनिक अधिकारी के किसी भी कार्य की शिकायत नहीं की जाती है, तो ऐसा अधिकारी धारा के संरक्षण का हकदार नहीं होगा, भले ही उसे प्रतिवादी के रूप में आरोपित किया गया हो। मुकदमे की प्रकृति पूरी तरह से वाद पत्र के संदर्भ में निर्धारित की जानी है। जहां वादी, विस्थापित भूमि का बंधक होने के नाते, केवल यह घोषणा करने की मांग करता है कि बंधक को निर्धारित अवधि के भीतर भुनाया नहीं गया है, तो मुकदमा संरक्षक के 'किसी भी कार्य के संबंध में' नहीं है, जिसे विस्थापित-बंधकों के हित का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिवादी के रूप में आरोपित किया गया है। यदि अभिरक्षक को नोटिस नहीं दिया जाता है तो संहिता की धारा 80 इस तरह के मुकदमे पर रोक नहीं है।

(पैरा 11, 15, 16 और 17)

यह माना जाता है कि जहां किसी बयान को धार्मिक संबंध व्यक्त करने के रूप में भरोसा किया जाता है, उसे यह दिखाना चाहिए कि यह इस तरह के धार्मिक संबंध को स्वीकार करने के इरादे से किया गया था, जब इसे बनाया गया था और स्वीकार करने का इरादा किसी शामिल या तर्क की दूर-दूर की प्रक्रिया द्वारा इसके निर्माता पर नहीं थोपा जा सकता है। जब ग्राम पटवारी को दी गई रिपोर्ट में इसे बनाने वाला व्यक्ति केवल उन अधिकारों का विवरण देता है जिन्हें उसने खरीदा या हस्तांतरित किया है और यह विवरण देने के माध्यम से वह ऐसे अधिकारों को बंधक अधिकार बताता है, तो वह जानबूझकर या यहां तक कि निहितार्थ द्वारा स्वीकार नहीं करता है कि बंधक मौजूद है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बंधक के लेन-देन में मोचन का अधिकार निहित है, लेकिन रिपोर्ट बनाने वाला व्यक्ति यह स्वीकार नहीं करता है कि बन्धककर्ताओं के मोचन का अधिकार उस समय मौजूद है जब पटवारी को रिपोर्ट की जाती है।

(पैरा 18)

श्री बी. एल. बलहोत्रा, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रोहतक, गुड़गांव की अदालत ने दिनांक 3 जून, 1960 *को अपने आदेश में श्री ईशर सिंह होरा, उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, गुड़गांव द्वारा दिनांक* 11 दिसम्बर, 1959 को वादी के *वाद को खारिज करते हुए मुकदमा खारिज कर दिया।*

दोनों न्यायालयों ने पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया।

आर. एस. मित्तल, अधिवक्ता, *आवेदकों के लिए।*

एच. एन. मेहतानी, सहायक महाधिवक्ता (हरियाणा), प्रतिवादियों *की ओर से* 5 *से* 30.

निर्णय

(एक) इस निर्णय से मैं वादी द्वारा पसंद की गई 1960 की दो नियमित द्वितीय अपील संख्या 1529 और 1530 का निपटान करूंगा जो क्रमशः 1958 के वाद संख्या 725 और 737 से उत्पन्न हुई हैं और जिनमें तथ्य समान हैं और कानून के बिंदुओं को समान करने की आवश्यकता है।

(दो) 1958 के वाद संख्या 725 में तीन वादी फूल खान के बेटे समद्, रहमत खान और सबन खान हैं। वे नगीना गांव, तहसील फिरोजपुर झिरका, जिला गुड़गांव में स्थित 4 *बीघा* 13 *बिस्वास* भूमि के मूल बंधकों के उत्तराधिकारी हैं और जिसमें खसरा संख्या 85, 95 और 490 शामिल हैं। वर्ष 1877 से लेकर मुकदमा शुरू होने की तारीख तक इस भूमि के इतिहास का पता दस्तावेज़ प्रदर्शनी पृष्ठ 1 में लगाया गया है, जो राजस्व रिकॉर्ड का एक अंश है। वर्ष 1888 में, भूमि को खसरा नंबर 74, 79 और 80 और 413 द्वारा नामित किया गया था, खसरा नंबर 74 और 79 तब एक मिस्टर अमीरी के स्वामित्व में थे और अन्य दो खसरा नंबर एक शजार्दी के पास थे। सुश्री अमीरी ने 19 जून, 1888 को तय किए गए म्यूटेशन नंबर 57 के तहत अपने दो खसरा नंबरों को श्रीमती जान बीबी के पक्ष में गिरवी रख दिया । खसरा नंबर 80 को शजार्दी ने हबीब उल्लाह के पक्ष में गिरवी रखा था और इस संबंध में म्यूटेशन नंबर 429 को 8 दिसंबर 1891 को मंजूरी दी गई थी। खसरा नंबर 413 के संबंध में शजार्दी द्वारा एक और बंधक बनाया गया था, बंधक इमाम खान और उनके भाई फूल खान थे, जो वादी के पिता थे। 17 दिसंबर 1896 को इस बंधक के संबंध में म्यूटेशन नंबर 1089 को मंजूरी दी गई थी।

(तीन) जब *वर्ष 1906-1907 के लिए जमाबंदी तैयार की गई, तो पूरी भूमि का स्वामित्व* शमिलात थुला काशब को हस्तांतरित कर दिया गया।

(चार) 31 मई, 1913 को उक्त फूल खान ने खसरा संख्या 74, 79 और 80 (जिसे तब तक क्रमशः खसरा संख्या

82, 90 और 91 के रूप में पुनर्नामित किया गया था) में मूल बंधक जान बीबी और हबीब उल्लाह के उत्तराधिकारियों श्री मजीदान और अन्य से बंधक अधिकार खरीदे। 17 अक्टूबर 1913 को उन्होंने ग्राम पटवारी को एक रिपोर्ट दी कि खेवट संख्या 398 (जिसमें खसरा संख्या 82 और 90 शामिल थे) में बंधक अधिकार उन्हें मौखिक लेनदेन के तहत बेचे गए थे और उन्होंने उक्त खसरा नंबरों का कब्जा प्राप्त कर लिया था। इस रिपोर्ट को उनके द्वारा चिह्नित किया गया था और इसके आधार पर 31 दिसंबर 1913 को उनके पक्ष में म्यूटेशन नंबर 1069 (प्रदर्शनी डी 2) को मंजूरी दी गई थी। इस बीच, यानी 3 नवंबर 1913 को, उन्होंने पटवारी को एक और रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा गया था कि खेवट नंबर 400 (जिसमें तब खसरा नंबर 80 शामिल था) में बंधक अधिकार हबीब उल्लाह की विधवा मजीदान द्वारा उन्हें बेच दिए गए थे और उन्होंने खसरा नंबर का कब्जा प्राप्त कर लिया था। इस रिपोर्ट को पटवारी ने लिखकर लिख दिया और फूल खान ने इस पर अंगूठा लगा दिया. 19 नवंबर 1913 को इस रिपोर्ट के अनुसरण में म्यूटेशन नंबर 1068 (प्रदर्शनी डी 1) को मंजूरी दी गई थी।

(पाँच) फुल खान और इमाम खान की मृत्यु के बाद, वादी ने विवाद में भूमि के बंधक के रूप में अपने जूते में कदम रखा।

(छः) 1958 के वाद संख्या 737 में वादी की संख्या चार है। वे ऊपर उल्लिखित फूल खान के तीन बेटे हैं, और एक दैंदर, गोदार का बेटा है। ये चारों उपरोक्त ग्राम नगीना में स्थित 4 बीघा भूमि के मूल बन्धकियों के उत्तराधिकारी हैं और जिनमें खसरा संख्या 470, 471, 673 और 674 शामिल हैं। वर्ष 1877 से वाद की स्थापना की तारीख तक इस भूमि का इतिहास राजस्व रिकॉर्ड (जो इस सूट में पी. 1 के रूप में भी प्रदर्शित किया गया है) को छोड़कर विवरण में उपलब्ध है। वर्ष 1877 में, भूमि को खसरा नंबर 398 और 581 द्वारा नामित किया गया था, जिसका मालिक एक माम राज था। 16 मई 1886 से कुछ समय पहले, भूमि को उनकी पत्नी श्रीमती अमीरी के मालिक-बंधक के रूप में और एक हुरमत खान को बंधक के रूप में परिवर्तित किया गया था। हुरमत खान ने खसरा संख्या 398 में अपने बंधक अधिकारों को एक मैन-उद-दीन के पक्ष में गिरवी रख दिया, - *16* मई, 1886 को तय किए गए म्यूटेशन नंबर 67 के तहत। 19 मई 1899 को, मैन-उद-दीन ने मौखिक रूप से फियाज़ी नाम की अपनी बेटी के पक्ष में उप-बंधक के रूप में अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया। 30 मई 1899 को, उन्होंने गांव के पटवारी को एक रिपोर्ट दी कि उन्होंने खसरा नंबर 398 में अपने बंधक अधिकारों को अपनी बेटी फियाजी को उपहार में दिया था, जिसे उन्होंने हस्तांतरित भी किया था।

उक्त खसरा नंबर का कब्जा। पटवारी ने रिपोर्ट दर्ज की जिस पर मैन-उद-दीन ने अपने हस्ताक्षर किए। म्यूटेशन नंबर 1839 (1958 के वाद संख्या 737 में प्रदर्शनी डी 1) को 6 अगस्त 1899 को उस रिपोर्ट के आधार पर मंजूरी दी गई थी।

(सात) जब *1906-1907 के 5 वें वर्ष के लिए अजमाबंदी तैयार की गई थी, तो विवाद में भूमि* को शमिलात थुला हशब को हस्तांतरित कर दिया गया था।

(आठ) हुरमत खान द्वारा मैन-उद-दीन के पक्ष में बनाए गए उप-बंधक को *31 दिसंबर, 1922 को तय किए गए म्यूटेशन नंबर 2940* के तहत पूर्व द्वारा भुनाया गया था।

(नौ) चारों वादी हुरमत खान बंधक के हित में हैं।

(दस) दोनों मुकदमों में प्रतिवादी समान हैं। इनकी संख्या 31 है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 गैर-विस्थापित हैं, जो नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 के नियम 8 के प्रावधानों के अनुसार खुद सहित *थुला हशब* के सभी सह-मालिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं (इसके बाद संहिता के रूप में संदर्भित)। प्रतिवादी संख्या 5 से 30 थुला के विस्थापित-मालिक हैं और उनका प्रतिनिधित्व इवैक्यूई प्रॉपर्टी, पंजाब (जिसे बाद में संरक्षक के रूप में जाना जाता है) और भारत संघ के संरक्षक द्वारा किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 31 पंजाब राज्य है जिसके स्थान पर अब पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के आधार पर हरियाणा राज्य ने कदम रखा है।

(ग्यारह) प्रत्येक मुकदमे में वादी ने दावा किया कि उन्होंने कस्टोडियन के साथ-साथ पंजाब राज्य को भी संहिता की धारा

80 के तहत नोटिस दिया था और एक घोषणा देने के लिए प्रार्थना की थी कि वे समय के साथ विवाद में भूमि के मालिक बन गए थे क्योंकि उपरोक्त बंधकों में से कोई भी इसके निर्माण से गणना किए गए 60 वर्षों की अवधि के भीतर भुनाया नहीं गया था।

(बारह) प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने फैसला कबूल किया। प्रतिवादी संख्या 5 से 30 की ओर से मुकदमे को कस्टोडियन द्वारा चुनौती दी गई थी, जिन्होंने दलील दी थी कि संहिता की धारा 80 के तहत उन्हें नोटिस के अभाव में इसे खारिज किया जा सकता है और क्योंकि यह अदालत द्वारा प्रतिबंधित है।

विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के प्रावधान, संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 की धारा 46 (जिसे बाद में प्रशासन अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) और विस्थापित हित (पृथक्करण) अधिनियम, 1951 (जिसे बाद में पृथक्करण अधिनियम कहा जाता है) के प्रावधानों द्वारा। गुण-दोष के आधार पर अभिरक्षक द्वारा यह कहा गया था कि वादी पर्चे द्वारा विवाद में भूमि के पूर्ण मालिक नहीं बन गए थे।

(तेरह)नीचे दिए गए दो न्यायालयों ने माना कि संहिता की धारा 80 के तहत संरक्षक को कोई नोटिस नहीं दिया गया था और मुकदमा केवल उसी आधार पर खारिज किया जा सकता है। उन्होंने आगे पाया कि 30 मई, 1899 को मैन-उद-दीन द्वारा और 17 अक्टूबर, 1913 और 3 नवंबर, 1913 को फूल खान द्वारा पटवारी को की गई रिपोर्टें भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 19 के अर्थ के भीतर संबंधित बंधकों के मोचन के अधिकार की लिखित में स्वीकृति के समान थीं। 1908, ताकि बंधक उन तारीखों से सीमा की नई अवधि (प्रत्येक मामले में 60 वर्ष) की गणना करने के हकदार बन गए। परिणाम, नीचे दिए गए न्यायालयों के अनुसार, था-

(१) कि ऊपर वर्णित सभी बंधक 29 अक्टूबर 1951 को जीवित थे, जब पृथक्करण अधिनियम लागू हुआ था,

(२) चूंकि बंधक बनाने वालों में से 26 विस्थापित थे, इसलिए भूमि में उनका हित संरक्षक में विस्थापित संपत्ति के रूप में निहित था ताकि भूमि स्वयं पृथक्करण अधिनियम की धारा 2 (डी) में परिभाषित उस अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर "समग्र संपत्ति" हो, और

(३) यह कि दोनों मुकदमों में वादी के दावे संयुक्त संपत्ति पर दावा करते हैं, अलगाव अधिनियम की धारा 20 दोनों मुकदमों की विचारणीयता के लिए एक बाधा थी।

(चौदह) इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए दोनों न्यायालयों द्वारा दो मुकदमों को खारिज कर दिया गया था।

(पंद्रह) वादी के वकील श्री मित्तल द्वारा उठाया गया पहला तर्क यह था कि संहिता की धारा 80 उन तथ्यों पर लागू नहीं होती है, जिनसे हम यहां संबंधित हैं क्योंकि दोनों में से कोई भी मुकदमा संरक्षक द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में स्थापित नहीं किया गया था। श्री मित्तल ने स्वीकार किया कि संरक्षक एक सार्वजनिक अधिकारी था, जिसे संहिता की धारा 80 के तहत कोई नोटिस नहीं भेजा गया था, लेकिन कहा कि कोई कार्य नहीं किया गया था।

अभिरक्षक के आधिकारिक या अन्यथा वादी द्वारा हमला किया गया था, जिन्होंने केवल विवाद में भूमि में स्वामित्व के अपने अधिकारों की घोषणा की मांग की थी। विवाद अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होता है। संहिता की धारा 80 इस प्रकार है:

80. ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी शासकीय क्षमता में किए जाने वाले किसी कार्य के संबंध में सरकार के विरुद्ध या लोक अधिकारी के विरुद्ध तब तक कोई वाद दायर नहीं किया जाएगा, जब तक कि लिखित में नोटिस दिए जाने के दो महीने बाद उसकी समाप्ति न हो जाए, या निम्नलिखित के कार्यालय में छोड़ न दी जाए-

(अ) केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमे के मामले में, सिवाय इसके कि यह रेलवे से संबंधित है, उस सरकार के सचिव;

(आ)केंद्र सरकार के खिलाफ एक मुकदमे के मामले में जहां यह एक रेलवे से संबंधित है, उस रेलवे के महाप्रबंधक;

(इ) किसी राज्य सरकार, उस सरकार के सचिव या जिले के कलेक्टर के विरुद्ध वाद के मामले में; और, एक सार्वजनिक

समद् आदि। सुभान खान आदि (कोशल, जे।

अधिकारी के मामले में, कार्रवाई का कारण, वादी का नाम, विवरण और निवास स्थान और वह राहत जो वह दावा करता है, बताते हुए उसे दिया गया या उसके कार्यालय में छोड़ दिया गया; और वाद में एक बयान होगा कि ऐसा नोटिस इस तरह दिया गया है या छोड़ दिया गया है।

(सोलह) ..... यह वाद-पत्र में है कि बारिट द्वारा बनाया गया है; यह धारा किसी लोक अधिकारी के खिलाफ मुकदमे के मामले को तभी संचालित करती है जब ऐसा मुकदमा "किसी भी अधिनियम के संबंध में" हो। यदि किसी मुकदमे में शिकायत की गई किसी अधिकारी ने शिकायत नहीं की है, तो ऐसे अधिकारी को धारा के संरक्षण का हकदार नहीं माना जाएगा, भले ही उसे प्रतिवादी के रूप में आरोपित किया गया हो। *रेवती मोहन दास* बहुत। *जतिंद्र मोहन घोष और अन्य* (1) उस मामले में तालुक राज नारायण सेन नामक एक संपत्ति पर एक बंधक राज मोहन गुप्ता द्वारा बनाया गया था, जो उस समय एस्टेट के सामान्य प्रबंधक थे, जिन्हें बंगाल किरायेदारी अधिनियम की धारा 95 के तहत नियुक्त किया गया था। राज मोहन गुप्ता की मृत्यु हो गई और उनके बाद हरिहर घोष नाम के एक व्यक्ति ने पदभार ग्रहण किया, जिसकी मृत्यु के बाद उनके बेटे जतिंद्र मोहन घोष को सामान्य प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था। बंधक बंधक धन की वसूली के लिए एक मुकदमा लाया।

(1) ए.आई.आर. 1934 पी.सी.

निचली अदालत ने इस मुकदमे की डिक्री की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस आधार पर अपील में इसे खारिज कर दिया था कि संहिता की धारा 80 के तहत जतिंद्र मोहन घोष को कोई नोटिस नहीं दिया गया था, जो एक सार्वजनिक अधिकारी थे। दूसरी अपील में प्रिवी काउंसिल के उनके लॉर्डशिप, जिनके समक्ष जतिंद्र मोहन घोष को प्रतिवादी नंबर 1 के रूप में पेश किया गया था, ने कहा:

"एक सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ मुकदमे के मामले में, यह केवल तभी होता है जब वादी अपनी आधिकारिक क्षमता में उसके द्वारा किए गए किसी कार्य की शिकायत करता है। प्रतिवादी 1 के वकील का तर्क है कि यह शर्त बंधक के निष्पादन से संतुष्ट थी, या, वैकल्पिक रूप से, बंधक का भुगतान करने में विफलता से। लॉर्डशिप की राय में इस विवाद की कोई भी शाखा वर्तमान मामले में धारा को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पहली शाखा पर यह इंगित करना पर्याप्त है कि बंधक प्रतिवादी 1 द्वारा निष्पादित नहीं किया गया था, बल्कि एक पूर्व प्रबंधक द्वारा किया गया था, और यह कि अपीलकर्ता बंधक के निष्पादन के किसी भी तरह से शिकायत नहीं करता है। ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय में यह दलील नहीं उठाई गई है ।

"वैकल्पिक तर्क पर, वे यह मानने में असमर्थ हैं कि प्रतिवादी 1 द्वारा भुगतान नहीं किया जाना प्रबंधक द्वारा 'अपनी आधिकारिक क्षमता में' किया जाने वाला कार्य है। सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 में निहित सामान्य परिभाषाओं के तहत, एक 'कार्य' में एक अवैध चूक शामिल हो सकती है, लेकिन वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से कोई अवैध चूक नहीं थी। यह देखना भी मुश्किल है कि ब्याज या मूलधन का भुगतान करने में केवल चूक प्रबंधक द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में किए जाने वाले कार्य को कैसे किया जा सकता है। बंधक ने प्रबंधक पर कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं लगाया, लेकिन केवल यह प्रावधान किया कि यदि भुगतान नहीं किया गया था तो बंधक अदालत के माध्यम से बिक्री द्वारा अपनी बकाया राशि का भुगतान करने का हकदार होगा, और यह सब अपीलकर्ता ^ ने अपने मुकदमे द्वारा मांगा था। कुछ समय के लिए प्रबंधक के पास बिक्री को बचाने के लिए भुगतान करने का विकल्प था, लेकिन एक विकल्प का उपयोग करने में विफलता किसी भी अर्थ में कर्तव्य का उल्लंघन नहीं है। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी 1 के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कोई दावा नहीं किया। वह केवल उस संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां थे जिसकी बिक्री की मांग की गई थी। लॉर्डशिप की राय में, इस तरह का मुकदमा धारा 80 के दायरे में नहीं है और मुकदमे के नोटिस की आवश्यकता नहीं थी।

इन टिप्पणियों में प्रतिपादित सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होता है। जैसा कि श्री मित्तल ने बताया, दोनों मुकदमों में वादी ने अभिरक्षक के किसी भी कृत्य पर हमला नहीं किया और इसलिए संहिता की धारा 80 किसी भी मुकदमे पर कोई रोक नहीं है।

(सत्रह) कस्टोडियन के वकील श्री मेहतानी ने बताया कि हालांकि दो मुकदमों में वादी ने संरक्षक के किसी भी कृत्य का उल्लेख नहीं किया था, जिसे वादी द्वारा चुनौती देने की मांग की गई थी, बाद में दोनों मुकदमों में अस्थायी निषेधाज्ञा

जारी करने के लिए आवेदन किए गए और उन आवेदनों में, उन्होंने कहा कि संरक्षक का इरादा वादी को विवाद में भूमि से बाहर करने का था और धमकी दी गई थी। उन आवेदनों की सामग्री के साथ, हम यहां चिंतित नहीं हैं, और मुकदमों की प्रकृति को पूरी तरह से संदर्भ के साथ निर्धारित किया जाना चाहिए, उन वादकों के संदर्भ में जिनमें कोई राहत नहीं मांगी गई थी जैसे कि दो आवेदनों में संरक्षक को जिम्मेदार ठहराने वाले प्रकार के इरादे या खतरे से प्रवाहित हो सकता है। दोनों मुकदमों में से प्रत्येक में वादी ने निषेधाज्ञा की राहत की मांग किए बिना केवल एक घोषणा की मांग की और, जैसा कि वादी का रुख है, यह नहीं कहा जा सकता है कि दोनों में से कोई भी मुकदमा संरक्षक द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में था। इसलिए, संहिता की धारा 80 को किसी भी मुकदमे के लिए रोक नहीं माना जा सकता है और इसके विपरीत नीचे दिए गए न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष को उलट दिया जाता है।

(अठ्ठारह) श्री मित्तल का अगला तर्क यह था कि मैन-उद-दीन और फूल खान द्वारा गांव के पटवारी को दी गई रिपोर्टों को इस तरह से नहीं माना जा सकता है कि भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 की धारा 19 के अर्थ के भीतर बंधकों के मोचन के अधिकार की स्वीकृति के बराबर है, और यह कि बंधककर्ता नहीं थे, इसलिए, रिपोर्ट बनाने की तारीखों से सीमा की नई अवधि की गणना करने के हकदार हैं। इस विवाद को भी अपवाद नहीं माना जाना चाहिए। जांच ाधीन सभी तीन रिपोर्टों में इसे बनाने वाले व्यक्ति ने केवल उन अधिकारों का विवरण दिया था जिन्हें उसने खरीदा या हस्तांतरित किया था, और यह उस विवरण को देने के माध्यम से था कि उसने ऐसे अधिकारों को बंधक अधिकार कहा था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोचन का अधिकार बंधक के लेनदेन में निहित है, लेकिन तब रिपोर्टों के लेखक जानबूझकर या यहां तक कि निहितार्थ से इस तरह के अधिकार का उल्लेख नहीं कर रहे थे और न ही यह स्वीकार कर रहे थे कि यह अस्तित्व में था। मामले के इस दृष्टिकोण में, उन्हें यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि बंधकों के मोचन का अधिकार उस समय मौजूद था।

जब रिपोर्ट तैयार की गई थी। तिलक *राम और अन्य बनाम तिलक मामले* में भी यही हुआ था । *नाथू और अन्य* (2) उस मामले में, जमीन के एक गिरवी धारक परमेश्वरदास ने चार दस्तावेजों में इस तथ्य का उल्लेख करते हुए बयान दिए कि वह इस तरह के बंधक हैं। इन दस्तावेजों में से एक मुकदमे में दायर लिखित बयान था। लिखित बयान में कहा गया था कि परमेश्वरदास ने भूमि को गिरवी रखने वाले के रूप में रखा था। एक अन्य दस्तावेज परमेश्वरदास द्वारा निष्पादित एक बिक्री विलेख था जिसके आधार पर उन्होंने अपने बंधक अधिकारों को दूसरों के पक्ष में बेच दिया। इस तर्क को खारिज करते हुए कि इन दस्तावेजों में भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 की धारा 19 के अर्थ के भीतर अभिस्वीकृति की राशि वाले बयान शामिल हैं, उनके लॉर्डशिप ने शापुर फ्रेडून माजदा बनाम *शापुर फ्रीडून माजदा* बनाम *भारत में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया।दुर्गा प्रसाद* (3):

> "यदि बयान काफी स्पष्ट है, तो न्यायिक संबंध को स्वीकार करने का इरादा इससे निहित हो सकता है, प्रश्न में प्रवेश, व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन परिस्थितियों और शब्दों में किया जाना चाहिए जिनसे न्यायालय यथोचित रूप से अनुमान लगा सकता है कि प्रवेश करने वाला व्यक्ति बयान की तारीख के अनुसार एक निर्वाह दायित्व का उल्लेख करना चाहता है।

और फिर लेट ने के लिए आगे बढ़े:

> "इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोचन का अधिकार बंधक के लेनदेन में सार और अंतर्निहित है। लेकिन विचाराधीन बयान को निर्वाह दायित्व या दावा किए गए अधिकार से संबंधित होना चाहिए। जहां बयान को जुरल संबंध व्यक्त करने के रूप में भरोसा किया जाता है, यह दिखाना चाहिए कि यह इस तरह के जुरल संबंध को स्वीकार करने के इरादे से बनाया गया था जब इसे बनाया गया था। यह इस प्रकार है कि जहां एक बयान स्पष्ट रूप से अपने अस्तित्व को स्वीकार करने के इरादे के बिना दिया जाता है, स्वीकार करने का इरादा इसके निर्माता पर तर्क की एक शामिल या दूर-दूर की प्रक्रिया द्वारा नहीं थोपा जा सकता है।

(उन्नीस) इन टिप्पणियों के आलोक में उनके लॉर्डशिप ने परमेश्वरदास द्वारा लिखित बयान में दिए गए बयानों और उनके द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख को बंधक के संदर्भ के रूप में व्याख्या की।

(दो) ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 935.

(तीन) ए.आई.आर. 1961 एस.सी. 1236.

अपने स्वयं के हित का वर्णन करने के उद्देश्य से, न कि किसी चेतना या इरादे से इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए कि विचाराधीन बंधक उस समय मौजूद थे। जहां तक मैन-उद-दीन और फूल खान द्वारा की गई रिपोर्टों पर की जाने वाली व्याख्या का सवाल है, यह मामला व्यावहारिक रूप से सभी चार बिंदुओं पर है। उन रिपोर्टों में उनके लेखकों की ओर से किसी इरादे का कोई सबूत नहीं होना चाहिए, ताकि वे यह स्वीकार कर सकें कि विचाराधीन बंधक मौजूद हैं और उन बंधकों के लिए किए गए संदर्भों को केवल उन अधिकारों के विवरण के माध्यम से बनाया जाना चाहिए जिन्हें अधिग्रहित या अलग किया जा रहा था।

(बीस) श्री मित्तल का अगला तर्क यह था कि पृथक्करण अधिनियम की धारा 2 दोनों मुकदमों की विचारणीयता पर कोई रोक नहीं है। इस संबंध में अधिनियम के जिन उपबंधों की जांच की जानी चाहिए, वे धारा 2 के खंड (ख) और (घ) तथा धारा 20 की उपधारा (1) हैं। इन्हें लाभ के साथ यहां सेट किया जा सकता है:

> "2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो, –
>
> (* * * *
>
> (ख) 'दावा' से किसी व्यक्ति द्वारा किया गया वह दावा अभिप्रेत है, जो किसी संपत्ति में किसी अधिकार, शीर्षक या हित का विस्थापित नहीं है-
>
> (१) संपत्ति में एक विस्थापित के सह-हिस्सेदार या भागीदार के रूप में; नहीं तो
>
> (२) संपत्ति में एक विस्थापित के हित के बंधक के रूप में; नहीं तो
>
> (३) एक बंधक के रूप में जिसने संपत्ति को गिरवी रखा है या एक विस्थापित के पक्ष में कोई ब्याज दिया है।
>
> और इसमें कोई अन्य हित शामिल है जो ऐसे व्यक्ति का किसी विस्थापित व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से हो सकता है, और जिसे इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।
>
> (घ) 'समग्र संपत्ति' से ऐसी कोई संपत्ति अभिप्रेत है जो या कोई ऐसी संपत्ति जिसमें कोई हित निहित है, को विस्थापित संपत्ति घोषित किया गया है या जिसे विस्थापित संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 के तहत अभिरक्षक में निहित किया गया है और
>
> (१) जिसमें विस्थापित के हित में उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के सहयोगी या भागीदार के रूप में आयोजित संपत्ति में एक अविभाजित हिस्सा शामिल है, न कि एक विस्थापित होने के नाते; नहीं तो
>
> (२) जिसमें विस्थापित का हित किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी रूप में बंधक के अधीन है, न कि एक विस्थापित होने के नाते; नहीं तो
>
> (३) जिसमें किसी व्यक्ति का हित, जो एक विस्थापित नहीं है, किसी भी रूप में एक विस्थापित के पक्ष में बंधक के अधीन है; नहीं तो
>
> (४) जिसमें एक विस्थापित व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से ऐसा अन्य हित है, न कि एक विस्थापित होने के नाते, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचित किया जा सकता है;
>
> "20 (1) इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से किए गए प्रावधान के अलावा, कोई भी सिविल या राजस्व न्यायालय किसी मुकदमे या कार्यवाही पर विचार नहीं करेगा, जहां तक यह समग्र संपत्ति के किसी दावे से संबंधित है, जिसे सक्षम अधिकारी को इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत निर्णय लेने का अधिकार है, और समग्र संपत्ति के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा की गई या की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के संबंध में कोई आदेश किसी सिविल द्वारा नहीं दिया जाएगा। अदालत या अन्य प्राधिकरण।

(इक्कीस) धारा 20 की उप-धारा (1) में बार संचालित होने से पहले, न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि विचाराधीन मुकदमा धारा 2 (डी) में परिभाषित समग्र संपत्ति के किसी भी दावे से संबंधित है और यह दावा धारा 2 (बी) के दायरे में आता है।

अब वादी द्वारा लाए गए दो मुकदमों में उनके द्वारा किया गया दावा उन व्यक्तियों द्वारा किया गया दावा है जो किसी संपत्ति में अधिकार या हित से विस्थापित नहीं हैं, क्योंकि वे विस्थापित व्यक्तियों के हितों के बंधक हैं। इसलिए, उनका दावा धारा 2 (बी) के खंड (ii) द्वारा कवर किए गए प्रकार का है। हालांकि, यह धारा 2 (डी) के अर्थ के भीतर विवाद में संपत्ति को "समग्र संपत्ति" बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसके अनुसार उस संपत्ति या उसमें ब्याज को विस्थापित संपत्ति घोषित किया जाना चाहिए या प्रशासन अधिनियम के तहत संरक्षक में निहित होना चाहिए। पार्टियों के बीच यह आम आधार था कि विवाद में भूमि या उसमें बंधकों के अधिकारों को कभी भी विस्थापित संपत्ति घोषित नहीं किया गया था। हालांकि, मेहतानी ने प्रस्तुत किया कि विवाद में भूमि *प्रशासन अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा* (2) के तहत संरक्षक में निहित थी, जो इस प्रकार है:

"8. (1) * * * *

(दो) जहां इस अधिनियम के लागू होने से ठीक पहले, किसी राज्य में कोई संपत्ति इसके द्वारा निरस्त किए गए किसी कानून के तहत संरक्षक की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति में विस्थापित संपत्ति के रूप में निहित थी, तो इस अधिनियम के लागू होने पर संपत्ति को इस अधिनियम के अर्थ के भीतर घोषित की गई विस्थापित संपत्ति माना जाएगा,

और इस अधिनियम के अधीन राज्य के लिए नियुक्त या नियुक्त समझे गए अभिरक्षक में निहित समझा जाएगा, और ऐसा करना जारी रखेगा:

* * * * *_"

(बाईस) इस उप-धारा का विश्लेषण मेरे द्वारा *भारत संघ बनाम भारत संघ* में *किया गया था।जोति प्रसाद* (4) ने प्रशासन अधिनियम द्वारा निरस्त की गई विस्थापित संपत्ति से संबंधित कानून के प्रावधानों के संदर्भ में और मैंने पाया कि जब तक किसी संपत्ति को 1949 के विस्थापित संपत्ति अध्यादेश, 27 के प्रशासन की धारा 7 के प्रावधानों के अनुपालन में विस्थापित संपत्ति घोषित नहीं किया जाता है, तब तक इसे संरक्षक में निहित माना जा सकता है यदि यह किसी व्यक्ति की संपत्ति थी। जो 18 अक्टूबर, 1949 से पहले एक विस्थापित बन गए थे, जिस तारीख को पूर्वी पंजाब विस्थापित संपत्ति (प्रशासन) अध्यादेश, 1949 को निरस्त किया गया था। जाहिर है, रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उस तारीख या तारीख को दिखाए जिस दिन प्रतिवादी नंबर 5 से 30 को निकाला गया था। यदि इनमें से किसी भी प्रतिवादी के मूल्यांकन की तारीख 18 अक्टूबर 1949 से पहले थी, तो उसकी संपत्ति को प्रशासन अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के कारण संरक्षक में निहित माना जाएगा। यदि, दूसरी ओर, वह तारीख 18 अक्टूबर 1949 थी, या उसके बाद, तो उस प्रतिवादी की संपत्ति को ऐसा निहित नहीं माना जाएगा। चूंकि प्रत्येक प्रतिवादी संख्या 5 से 30 के मामले में तारीख अदालत को उपलब्ध नहीं कराई गई है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि भूमि में एक बंधक के रूप में उसकी रुचि संरक्षक में निहित है। ऐसा होने पर, धारा 2 (डी) में निहित समग्र संपत्ति की परिभाषा के मुख्य अवयवों में से एक विवाद में भूमि के मामले में कमी है।

(तेईस) जैसा कि इस्माइल, जे. ने सुश्री *खैर-उन-निसा वी में बताया* है। *इवैक्यूई संपत्ति के संरक्षक* (5):

"एक सामान्य सिद्धांत के रूप में, सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के बहिष्करण का अनुमान आसानी से नहीं लगाया जाना चाहिए। यदि कोई विशेष पक्ष यह तर्क देता है कि सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा गया है, तो इसे स्थापित करने की जिम्मेदारी उस पक्ष पर है और इस तरह के बहिष्करण को तब तक स्थापित नहीं कहा जा सकता है जब तक कि सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर प्रावधान की आवश्यकताओं का किसी विशेष मामले में सख्ती से पालन नहीं किया जाता है।

(चार) 1960 के आर.एस.ए. 1261 का निर्णय 28 जुलाई 1971 को हुआ।

(पाँच) ए.आई.आर. 1968 दिल्ली 162.

(चौबीस) विवाद वाली भूमि को समग्र संपत्ति नहीं दिखाया गया है, यह माना जाना चाहिए कि "दो मुकदमों पर

विचार करने के लिए सिविल अदालतों का अधिकार क्षेत्र पृथक्करण अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों के कारण निषिद्ध नहीं है।

(पच्चीस) श्री मेहतानी के अनुसार, प्रशासन अधिनियम की धारा 46 के तहत मुकदमों पर रोक लगा दी गई थी, भले ही पृथक्करण अधिनियम की धारा 20 उनके रास्ते में न खड़ी हो। उक्त धारा 46 का खंड (ए) सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को "किसी भी सवाल पर विचार करने या निर्णय लेने के लिए छीन लेता है कि क्या कोई संपत्ति या किसी संपत्ति में कोई अधिकार या हित विस्थापित संपत्ति है या नहीं" और श्री मेहतानी का तर्क यह था कि यह न्यायालय इस सवाल को निर्धारित नहीं कर सकता था कि प्रतिवादी संख्या 5 से 30 की संपत्ति विस्थापित संपत्ति थी या नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह विवाद अपवाद नहीं है। जैसा कि *कस्टोडियन इवैक्यूई प्रॉपर्टी, पंजाब और अन्य में निर्धारित किया गया* है।*जाजरान बेगम* (6), प्रशासन अधिनियम की धारा 46 बहुत व्यापक रूप से लिखी गई है और इसमें निर्दिष्ट मामलों में सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से रोकती है। हालांकि, यह विवाद श्री मेहतानी के मामले में मददगार नहीं है, क्योंकि खंड (ए) उपरोक्त केवल दो प्रश्नों के मनोरंजन या निर्णय पर रोक लगाता है, जैसा कि *जाफरान बेगम के मामले* (6) (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप द्वारा बताया गया है:

(१) क्या कोई विशेष व्यक्ति विस्थापित हो गया है या नहीं और

(२) क्या विवाद में संपत्ति ऐसे व्यक्ति की है।

कस्टोडियन की ओर से दिए गए प्रस्ताव के साथ कि प्रतिवादी नंबर 5 से 30 विस्थापित हैं और विवाद में बंधक-अधिकार उनके थे ताकि प्रतिवादी नंबर 5 से 30 की निकासी की तारीख तक वे अधिकार विस्थापित संपत्ति बन जाएं, श्री मित्तल का कोई झगड़ा नहीं है और वास्तव में स्वीकार करते हैं कि उन अधिकारों को खंड ((च) प्रशासन अधिनियम की धारा 2 हालांकि, उनका तर्क है कि सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के सवाल के संबंध में निर्धारण की आवश्यकता एकमात्र बिंदु यह है कि क्या उक्त बंधक-अधिकार, विस्थापित संपत्ति होने के नाते, कभी भी प्रशासन अधिनियम की धारा 8 के तहत संरक्षक में निहित हैं, और इस तरह के निहित, वह प्रस्तुत करते हैं, मनोरंजन या निर्णय का मामला नहीं है, जिस पर सिविल न्यायालयों द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है।

(6) ए.आई.आर. 1968 एस.सी.

प्रशासन अधिनियम की धारा 46 विद्वान वकील द्वारा दिए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, मैं श्री मित्तल से सहमत होने के लिए पूरी तरह से इच्छुक हूं। प्रशासन अधिनियम की धारा 2 के खंड (एफ) में परिभाषित 'विस्थापित संपत्ति' एक बात है, और इसका अभिरक्षक में निहित होना बिल्कुल दूसरी बात है, जैसा कि उस अधिनियम की धारा 8 में नियोजित भाषा से स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है कि संपत्ति को संरक्षक में तभी निहित माना जाएगा जब दो शर्तों में से एक या दूसरी पूरी हो जाती है। उन शर्तों में से एक यह है कि ऐसी संपत्ति को उस अधिनियम की धारा 7 के तहत विस्थापित संपत्ति घोषित किया जाना चाहिए। दूसरी शर्त में कहा गया है कि ऐसी संपत्ति प्रशासन अधिनियम द्वारा निरस्त किए गए किसी भी कानून के तहत संरक्षक में निहित होनी चाहिए। यह धारा इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ती है कि कोई संपत्ति, भले ही वह प्रशासन अधिनियम की धारा 2 के खंड (एफ) के अर्थ के भीतर विस्थापित संपत्ति हो, को संरक्षक में निहित नहीं माना जाएगा, जब तक कि इसे उस अधिनियम की धारा 7 के तहत विस्थापित संपत्ति घोषित नहीं किया गया था या उस अधिनियम द्वारा निरस्त किए गए किसी भी कानून के तहत संरक्षक में निहित नहीं किया गया था। इस प्रकार किसी संपत्ति के खाली की गई संपत्ति होने का सवाल अभिरक्षक में निहित संपत्ति से अलग है और बाद वाले को प्रशासन अधिनियम की धारा 46 के खंड (ए) द्वारा प्रतिबंधित मनोरंजन या निर्णय के प्रश्न के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(छब्बीस) मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, सिविल न्यायालयों द्वारा पार्टियों के बीच विवाद के अधिनिर्णय पर कोई कानूनी रोक नहीं है और इसके विपरीत नीचे दिए गए न्यायालयों के निष्कर्ष उलट दिए गए हैं।

(सत्ताईस) क्या प्रत्येक अपील में अपीलकर्ता विवादित भूमि के मालिक बन गए हैं, यह देखा जाना बाकी है। भारतीय परिसीमा

अधिनियम, 1908 द्वारा बंधक संपत्ति के मोचन के लिए अनुमत सीमा की अवधि रिडीम के अधिकार के उपार्जन की तारीख से 60 वर्ष थी। वर्ष 1956 के अंत तक, ऊपर वर्णित सभी चार बंधकों के संबंध में उस अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार प्रत्येक मामले में वादी अपने कब्जे में बंधक भूमि के पर्चे से पूर्ण मालिक बन गए और उस आशय की घोषणा के हकदार हैं।

(अठ्ठाईस) परिणाम में अपील सफल होती है और स्वीकार की जाती है। निचली अदालतों के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया जाता है और दोनों मुकदमों में से प्रत्येक में वादी को उनके द्वारा प्रार्थना की गई घोषणा दी जाती है। पार्टियों को अपनी लागत पूरी तरह से वहन करनी होगी।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा |

अमृतबीर कौर
प्रक्षिशु न्यायिक अधिकारी
अससंध, कर्नल
हरियाणा